स्विस बैंकों में अवैध जमा रखने वाले भारतीयों पर होगी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई- जेटली

नई दिल्ली-केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने चेतावनी दी कि स्विस बैंकों में अवैध रुप से धन जमा कराने वाले भारतीयों की पहचाना छुपाना अब मुश्किल होगा और ऐसे लोगों पर कालाधन रोधी कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से वहां भारतीयों के खातों के बारे में तत्काल स्विट्जरलैंड से सूचनाओं का मिलना शुरू हो जाएगा।स्विस नेशनल बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारतीयों द्वारा जमा कराए जाने वाले धन में 50त्न से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारतीयों का स्विस बैंक में 7,000 करोड़ रुपये जमा था जबकि इससे पिछले लगातार तीन साल वहां भारतीयों की जमा में गिरावट दर्ज की गयी थी। जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा, ''आज एक खबर छपी है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़ा है। इसकी वजह से कुछ हलकों से गलत जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया आयी और इसने सरकार के कालाधन रोधी कदमों के प्रयासों के परिणाम पर सवाल खड़े किए हैं।''

उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड हमेशा से जानकारियों को साझा करने में अनिच्छुक रहा है। आल्पाइन देशों ने अपने घरेलू कानूनों को संशोधित किया है जिनमें सूचना सार्वजनिक करने के नियम भी शामिल हैं। इन देशों ने भारत के साथ वास्तविक समय में जानकारियां साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे भारत को उसी समय जानकारी मिल जाएगी जब कोई भारतीय वहां धन जमा करेगा। जेटली ने कहा कि जनवरी 2019 से यह जानकारी आने लगेगी। अवैध रुप से धन जमा करने वाले किसी भी जमाकर्ता को यह पहले से पता होगा कि कुछ महीनों में उनका नाम सार्वजनिक होना ही है और उन पर भारत में कालाधन रोधी कानूनों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले पर सार्वजनिक बहस कर रहे हैं उन्हें इन आधारभूत तथ्यों को समझना चाहिए, बजाय कोई कम या गलत जानकारी वाला दृष्टिकोण रखें। जेटली ने कहा कि कर विभाग द्वारा पहले की गई जांच में पाया गया कि इनमें उन लोगों का धन भी शामिल है जो भारतीय मूल के हैं लेकिन अब किसी दूसरे देश के नागरिक हैं और इसमें गैर-निवासी भारतीयों का धन भी शामिल है।

अगर करना चाहते हैं अपने बेटे की शादी तो बनवा लें शौचालय

चंडीगढ़-अक्षय कुमार अभिनीत 'टॉयलेट- एक प्रेम कथा' से प्रेरित होकर हरियाणा के सिरसा जिले की एक गांव पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि वे अपनी बेटियों की शादी ऐसे परिवारों में नहीं करेंगे जिनके घरों में शौचालय नहीं है। सरपंच धर्मपाल मुंडलिया ने आज बताया कि इस महीने की शुरूआत में गोडिकान गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया।

उन्होंने बताया कि पंचायत ने आठ जून को यह प्रस्ताव पारित किया था। हरियाणा सरकार ने राज्य के गांव सरपंचों को 'स्वच्छ भारत' की ओर काम करने के लिए प्रेरित करने और स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए 'टॉयलेट-एक प्रेम कथा' फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि गांव के निवासी अपनी बेटियों और बहनों की शादी केवल उन परिवारों में करेंगे जिनके घरों में शौचालय बने होंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायत को उसके फैसले के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच मुक्त भारत और हर घर में शौचालय की कल्पना करता है। गोडिकान गांव का फैसला सच में सराहनीय है।' उन्होंने कहा कि अन्य पंचायतों को भी इस प्रस्ताव का पालन करना चाहिए।

नशे का सेवन करने वालों से सख़्ती से निपटे पंजाब सरकार-अकाल तख़्त

अमृतसर-पंजाब में नशे के अत्यधिक मात्रा में सेवन से लोगों के मरने की खबरों के बीच अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने पंजाब सरकार से प्रदेश में इस खतरे से सख्ती से निपटने की अपील की। अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि इस खतरे से निपटना पंजाब पुलिस और राज्य सरकार कर्तव्य है। लुधियाना की एक युवती को जबरदस्ती नशे में धकेलने के आरोप में पुलिस ने उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को निलंबित करने के बाद उपजे विवादों के बीच सिंह ने कहा कि पुलिस में भी कुछ 'काले भेड़' हैं जिनकी पहचान करने तथा उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को नशे से बचाया जाए।

उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी को समर्थन देने वाले लोगों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से नशे के आदि हो चुके युवाओं को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और काउंसलिंग करने की अपील की। खबरों के अनुसार पंजाब के फरीदकोट और अमृतसर जिले में पिछले दो हफ्तों में नशे के कारण दो लोगों की मौत हो चुकी है।

हिंदू-मुस्लिम दंपती की शिकायत पर विदेश मंत्रालय ने लिया एक्शन, मांगी रिपोर्ट

नई-दिल्ली-लखनऊ के पासपोर्ट सेवा केन्द्र के एक अधिकारी के खिलाफ एक हिन्दू-मुस्लिम दंपती ने उत्पीड़न तथा अपमान किये जाने की शिकायत की थी , इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। हिन्दू-मुस्लिम दंपती मोहम्मद अनस सिद्दीकी और उनकी पत्नी तन्वी सेठ ने ट्विटर पर पूरा घटनाक्रम लिखा था और उसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को टैग किया था। उनकी शिकायत के जवाब में 'काउंसलर, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग' के सचिव डीएम मुले ने कहा कि उन्होंने लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

मुले ने ट्विटर पर लिखा, 'आपको परेशानी हुई, इसका हमें दुख है। मैंने लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र से रिपोर्ट मांगी है, उचित कार्रवाई की जाएगी।' सिद्दीकी और सेठ ने 19 जून को पासपोर्ट के लिए आवेदन दिए थे और लखनऊ पासपोर्ट केंद्र पर 20 जून का समय लिया था। दंपती के मुताबिक उनका आवेदन खारिज करने से पहले पासपोर्ट अधिकारी विकास मिश्रा ने कथित तौर पर उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया।

सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा है कि वह और उनकी पत्नी इस क्रूरता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। सेठ ने ट्वीट किया, '@SushmaSwaraj नमस्ते मैडम, मैं यह ट्वीट न्याय और आपमें अपने अटूट विश्वास, साथ ही यह विडंबना है कि दिल में गुस्से और दुख तथा पीड़ा के साथ टाइप कर रही हूं। इसकी वजह है रतन स्क्वेयर स्थित लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में विकास मिश्रा द्वारा मेरे साथ किया गया बर्ताव, इसलिए क्योंकि मैंने एक मुस्लिम से शादी की और अपना नाम नहीं बदला।'

उन्होंने लिखा कि अधिकारी ने उनके साथ बहुत रूखा बर्ताव किया , वह उनके मामले पर बात करते हुए इतना ऊंचा बोल रहे थे कि अन्य लोग भी उसे सुन पा रहे थे। सेठ ने कहा, 'इससे पहले मैंने कभी भी इतना प्रताड़ित महसूस नहीं किया। कार्यालय के अन्य कर्मचारियों ने भी माना कि उनका बर्ताव बहुत रूखा था।'

हज सब्सिडी खत्म होने के बावजूद हवाई यात्रा पर खर्चा होगा कम- नकवी

नई-दिल्ली-केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी खत्म किये जाने बावजूद इस बार हजयात्रियों की हवाई यात्रा पर पिछले साल के मुकाबले 57 करोड़ रुपये कम खर्च होंगे। हज कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट हज ऑफिसर, हज असिस्टेंट के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में नकवी ने कहा कि 2017 में 1 लाख 24 हजार 852 हजयात्रियों के लिए 1030 करोड़ रूपए एयरलाइन्स कंपनियों को हवाई किराये के रूप में दिए गए थे जबकि 2018 में हज कमेटी के माध्यम से जाने वाले 1 लाख 28 हजार 702 हजयात्रियों के लिए 973 करोड रूपए दिए जायेंगे जो पिछले वर्ष के मुकाबले 57 करोड़ रूपए कम है।

नकवी ने कहा कि इस वर्ष हज के लिए कुल 3 लाख 55 हजार 604 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमे 1 लाख 89 हजार 217 पुरुष और 1 लाख 66 हजार 387 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत से पहली बार मुस्लिम महिलाएं बिना 'मेहरम' (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जा रही हैं। बिना 'मेहरम' के हज पर 1308 महिलाएं जा रही हैं। नकवी ने कहा कि पहली बार हज यात्रियों को अपने मूल इम्बार्केशन पॉइंट (प्रस्थान स्थल) के अलावा किसी एक अन्य इम्बार्केशन पॉइंट से भी जाने की सुविधा दी गई है जिसके उत्साहजनक नतीजे आए हैं।

मंत्री ने कहा कि हज सब्सिडी खत्म होने और सऊदी अरब में विभिन्न नए करों के बावजूद आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा भारतीय मुस्लिम 2018 में हज यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत से रिकॉर्ड 1 लाख 75 हजार 25 मुसलमान हज 2018 के लिए जायेंगे। इस वर्ष हज पर जाने वालों में रिकॉर्ड 47 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।

नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी खत्म होने और सऊदी अरब में विभिन्न करों में वृद्धि के बावजूद भारत से जाने वाले हज यात्री पर कोई नाजायज बोझ नहीं पड़ने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से 6700, औरंगाबाद से 350, बेंगलुरु से 5550, भोपाल से 254, कोचीन से 11700, चेन्नई से 4000, दिल्ली से 19000, गया से 5140, गोवा से 450, गुवाहाटी से 2950, हैदराबाद से 7600, जयपुर से 5500, कोलकाता से 11610, लखनऊ से 14500, मंगलौर से 430, मुंबई से 14200, नागपुर से 2800, रांची से 2100, श्रीनगर से 8950, वाराणसी से 3250 लोग इस वर्ष हर्ष पर जा रहे हैं, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या होगी।

मंत्री के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को दिल्ली, गया, गुवाहाटी, लखनऊ और श्रीनगर से हज यात्री रवाना होंगे। 17 जुलाई 2018 को कोलकाता से, 20 जुलाई को वाराणसी से, 21 जुलाई को मंगलोर से, 26 जुलाई को गोवा से, 29 जुलाई को औरंगाबाद, चेन्नई, मुंबई, नागपुर से, 30 जुलाई को रांची से, 01 अगस्त को अहमदाबाद, बंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, जयपुर से और 03 अगस्त को भोपाल से हज यात्री रवाना होंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक-रवि कुमार पोत्दार, 71/74, सुयश विहार, भमोरी दुबे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिस, 864/9, नेहरु नगर, इन्दौर म०प्र० से मुद्रीत
प्रधान संपादक-रवि कुमार पोत्दार आर.एन.आई. नम्बर-12782/2003 e-mail- censortimes@ hotmail.com Mob No-9926631707